पंचदश

बिहार विधान-सभा

चतुर्दश सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग-5

शुक्रवार, तिथि 03 श्रावण 1936 (श0) / 25 जुलाई, 2014 (ई0)

प्रश्नों की कुल संख्या 05

(1) ऊर्जा विभाग	..	..	01
(2) स्वास्थ्य विभाग	..	..	03
(3) योजना एवं विकास विभाग	..	..	01
		कुल योग —	05

प्लेटलेट्स प्लाज्मा उपलब्ध कराना

30. श्री अरूण शंकर प्रसाद--क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पी0एम0सी0एच0, मॉडल ब्लड बैंक जयप्रभा अस्पताल, रेडक्रॉस ब्लड बैंक तथा महावीर कैंसर संस्थान, पटना में रक्त से रक्त अवयव अर्थात् प्लेटलेट्स प्लाज्मा निकालने के लिये थ्री बैग की सप्लाई नहीं होने के कारण यह कार्य मार्च महीना से बंद है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त अस्पतालों में थ्री बैग उपलब्ध कराकर मरीजों को रक्त का प्लेटलेट्स प्लाज्मा उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

उपयोग करना

31. श्री (डॉ0) अच्युतानन्द--दैनिक समाचार-पत्र के दिनांक 13 जून, 2014 के अंक में छपी "नक्सलग्रस्त जिलों में सात माह में भी नहीं बन सकी कार्य योजना" खबर के आलोक में क्या मंत्री, योजना एवं विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों के लिये अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता योजना के अधीन राज्य के 11 उग्रवाद प्रभावित जिलों के विकास हेतु कार्य योजना भेजने का निर्देश योजना आयोग द्वारा अक्टूबर, 2013 में राज्य सरकार को दिया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि उपरोक्त योजना के लिये 793 करोड़ रुपये का आवंटन राज्य सरकार को अक्टूबर, 2013 में ही प्राप्त हो गया था ;

(3) क्या यह बात सही है कि कार्य योजना केन्द्र सरकार को अभीतक नहीं भेजने के कारण उपरोक्त राशि का उपयोग नहीं किया जा सका है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो आवंटन प्राप्त राशि का 9 महीने के बाद भी उपयोग नहीं करने का क्या औचित्य है ?

प्रभारी मंत्री--(1) उत्तर अस्वीकारात्मक है। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों के लिये अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता अन्तर्गत योजना आयोग, भारत सरकार के पत्रांक 13053/6/2/2013 एम0एल0पी0, दिनांक 12 जुलाई, 2014 द्वारा निर्गत संशोधित मार्गदर्शिका में वार्षिक कार्य योजना तैयार कर भारत सरकार, योजना आयोग, नई दिल्ली को भेजने का प्रावधान नहीं है।

(2) उत्तर अस्वीकारात्मक है। वस्तुतः 793.00 करोड़ रुपया का आवंटन राज्य सरकार को एकमुश्त प्राप्त नहीं हुआ है। बल्कि यह राशि वर्ष, 2010-11 से वर्ष, 2013-14 तक निम्न रूप से वर्षवार प्राप्त हुई है :-

वर्ष	प्राप्त आवंटन (राशि करोड़ में)
2010-11	175.00
2011-12	270.00
2012-13	190.00
2013-14	158.38
कुल	793.38

(3) उत्तर अस्वीकारात्मक है।

(4) उत्तर अस्वीकारात्मक है। वर्ष, 2010-11 से वर्ष, 2013-14 तक प्राप्त कुल राशि 793.00 करोड़ रुपये के विरुद्ध 674.22 करोड़ रुपया व्यय किया जा चुका है।

कार्रवाई करना

32. श्री विक्रम कुँवर--दिनांक 12 जुलाई, 2014 को दैनिक समाचार-पत्र में प्रकाशित "अवैध दवा रखने में जिसे पकड़ा उसे ही लाईसेंस" शीर्षक को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि 22 सितम्बर, 2010 को पटना के एस0 पी0 वर्मा रोड में औषधि नियंत्रक विभाग ने श्री हनुमान एजेंसी के दो गोदाम से भारी मात्रा में एक्सपाइरी दवाएँ बरामद की थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि 9 जुलाई, 2014 को उसी एजेंसी के तीन गोदाम में छापेमारी की गयी, इसमें एक गोदाम से एक्सपाइरी हो चुकी सरकारी अस्पतालों में आपूर्ति की गयी दवाएँ बरामद की गयी ;

(3) क्या यह बात सही है कि वर्ष, 2010 में उक्त एजेंसी के संचालक के विरुद्ध पीरबहोर थाना में मामला दर्ज किया गया था, इसके बावजूद भी 2 अप्रैल, 2014 को विभाग द्वारा नया लाईसेंस जारी कर दिया गया ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार एक्सपाइरी दवाएँ बेचने वाले उक्त एजेंसी पर कार्रवाई करने एवं पुनः लाईसेंस देने वाले पदाधिकारी के विरुद्ध कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति कराना

33. श्री रामबालक सिंह--क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि स्वास्थ्य विभाग के संकल्प सं0 94 (14), दिनांक 7 फरवरी, 2007 द्वारा राज्य के पदाधिकारियों को किसी भी अस्पताल में चिकित्सा कराने पर चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति करने का प्रावधान है ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य के कर्मचारियों को केवल सरकारी अस्पताल एवं सी0जी0एच0एस0 से मान्यता प्राप्त अस्पतालों में कराई गई चिकित्सा की प्रतिपूर्ति की जाती है, जबकि राज्य में सी0जी0एच0एस0 से मान्यता प्राप्त अस्पतालों की संख्या कम होने के कारण अल्पवेतन भोगी कर्मचारी को अपना एवं अपने आश्रितों के उपचार में कठिनाई होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य के कर्मचारियों को भी किसी भी अस्पताल में चिकित्सा कराने पर चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

34. श्री मंजीत कुमार सिंह--दैनिक समाचार-पत्र दिनांक 11 मई, 2014 के अंक में प्रकाशित समाचार "बिजली कट रोकने को मिले 565 करोड़ 6 लाख खर्च ही नहीं" शीर्षक को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि केन्द्र सरकार से वर्ष, 2008 में पुनर्गठित त्वरित विद्युत् विकास एवं सुधार कार्यक्रम के तहत् पटना को बिजली कट से मुक्ति दिलाने के लिये 565 करोड़ की राशि बिहार सरकार को दी गई थी, जिसमें यह शर्त अंकित था कि दिसम्बर, 2010 तक काम पूरा नहीं होने पर राशि केन्द्र को सूद सहित लौटानी होगी ;

(2) क्या यह बात सही है कि अबतक यह कार्य पूरा नहीं हुआ है, जिससे पटना में प्रतिदिन बिजली कट होती है और उपलब्ध राशि भी सूद सहित केन्द्र सरकार को वापस करनी है, यदि हाँ, तो इस कार्य में लगे कम्पनियों, संवेदकों एवं सरकारी कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई हेतु सरकार की क्या योजना है ?

पटना :
दिनांक 25 जुलाई, 2014 (ई0) ।

हरे राम मुखिया,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान-सभा ।

बि0स0मु0 (एल0ए0), 78-डी0टी0पी0-450